

18 हजार करोड़ के पार पहुंचा मोबाइल व एसेसरीज कारोबार

मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में दिखी आगे निकलने की होड़, 3200 करोड़ का राजस्व सरकार की झोली में गया

रणजीत मिश्रा

नोएडा। उत्तर प्रदेश का नोएडा जिला मोबाइल फोन और एसेसरीज के कारोबार में देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र में करीब 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया, जिसने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

इस शानदार प्रदर्शन के साथ सरकार को इस इंडस्ट्री से लगभग 3200 करोड़ रुपये का टैक्स राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। यह नोएडा के औद्योगिक विकास और सरकारी नीतियों की सफलता का प्रमाण है। नोएडा में मोबाइल फोन और एसेसरीज के निर्माण और वितरण में कई दिग्गज कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी और लावा जैसी कंपनियां शामिल हैं। इनके बीच बाजार हिस्सेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। कंपनियों ने नवीनतम तकनीक, किफायती दाम और आकर्षक डिजाइन के साथ

टैक्स छूट समेत अन्य सुविधाओं से मिला प्रोत्साहन

स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों ने इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैक्स छूट, बेहतर बुनियादी ढांचा और निवेश-अनुकूल माहौल ने कंपनियों को नोएडा में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा का यह कारोबार अगले कुछ वर्षों में और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि 5जी तकनीक और स्मार्ट डिवाइस की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। जिससे नोएडा शहर अब वैश्विक स्तर पर मोबाइल उद्योग में एक बड़ा नाम बन चुका है।



इन प्रमुख मोबाइल कंपनियों के टैक्स से भरा सरकारी खजाना



कंपनी	जमा कराया गया कुल टैक्स
ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1141.47 करोड़ रुपये।
सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड	407.99 करोड़ रुपये।
वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	171.17 करोड़ रुपये।
लांगचीयर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	436.13 करोड़ रुपये।

ग्राहकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

इस प्रतिस्पर्धा ने न केवल उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर किया, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प भी प्रदान किए। नोएडा के सेक्टर - 63,

81 और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में बने अत्याधुनिक कारखानों ने इस कारोबार को गति दी। इन इकाइयों में लाखों स्मार्टफोन, चार्जर, ईयरफोन और अन्य एसेसरीज का उत्पादन हुआ, जो देश के साथ-साथ विदेशी बाजारों में

भी निर्यात किए गए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन कंपनियों ने स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले।

“

मोबाइल एंड एसेसरीज निर्माण से जुड़ी कंपनियों का उत्पादन और निर्यात में लगातार बढ़ती दर्ज की जा रही है। जिससे जीएसटी विभाग को भी टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये राजस्व के रूप में मिला है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग को करीब 3200 करोड़ से अधिक राजस्व टैक्स के रूप में इन कंपनियों से प्राप्त हुआ है। - संदीप भाग्या, अपर आयुक्त राज्य कर नोएडा जोन, गौतमबुद्ध नगर।